

A-0981

Total Pages : 5

Roll No.

BAPA(N)-220

सामाजिक कल्याण प्रशासन

Examination, June 2025

Time : 2:00 Hrs.

Max. Marks : 70

Note :- This paper is of Seventy (70) marks divided into two (02) Sections 'A' and 'B'. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein. *Candidates should limit their answers to the questions on the given answer sheet. No additional (B) answer sheet will be issued.*

नोट : यह प्रश्न-पत्र सत्तर (70) अंकों का है, जो दो (02) खण्डों 'क' तथा 'ख' में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है। *परीक्षार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका तक ही सीमित रखें। कोई अतिरिक्त (बी) उत्तर-पुस्तिका जारी नहीं की जायेगी।*

Section–A

(खण्ड–क)

Long Answer Type Questions

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

2×19=38

Note :– Section ‘A’ contains Five (05) Long-answer type questions of Nineteen (19) marks each. Learners are required to answer any *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड ‘क’ में पाँच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. What is the definition of social administration, and what is its scope in terms of managing and implementing social policies and programs?

सामाजिक प्रशासन की परिभाषा क्या है, और सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों के प्रबंधन और कार्यान्वयन के संदर्भ में इसका क्षेत्र क्या है?

2. How do Gulick’s principles of POSDCORB address the complexities of contemporary social administration, and how can these principles be adapted to current public sector challenges?

गुलिक के POSDCORB सिद्धांत समकालीन सामाजिक प्रशासन की जटिलताओं को कैसे संबोधित करता है, और इन सिद्धांतों को

वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र की चुनौतियों के लिए कैसे अनुकूलित किया जा सकता है?

3. Discuss the role of social justice in addressing systemic inequalities and compare it with the role of social legislation in creating laws and policies to regulate social behavior and protect rights.

प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने में सामाजिक न्याय की भूमिका पर चर्चा कीजिए और सामाजिक व्यवहार को विनियमित करने और अधिकारों की रक्षा के लिए कानून और नीतियां बनाने में सामाजिक कानून की भूमिका से इसकी तुलना कीजिए।

4. Analyze the role of the Ministry of Empowerment in implementing programs aimed at empowerment and inclusion, and how it aligns with the broader goals of achieving social justice in the country.

सशक्तिकरण और समावेशन के उद्देश्य से कार्यक्रमों को लागू करने में अधिकारिता मंत्रालय की भूमिका का विश्लेषण करें और यह देश में सामाजिक न्याय प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित होता है।

5. Discuss the role and functions of the Human Rights Commission in safeguarding and promoting human rights.

मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन में मानवाधिकार आयोग की भूमिका और कार्यों पर चर्चा कीजिए।

Section-B

(खण्ड-ख)

Short Answer Type Questions

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

4×8=32

Note :- Section 'B' contains Eight (08) Short-answer type questions of Eight (08) marks each. Learners are required to answer any *four* (04) questions only.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल **चार** (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. What are the key features of social administration?
सामाजिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
2. Which part of the Indian Constitution outlines the idea of India as a welfare state?
भारतीय संविधान का कौन सा भाग एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत के विचार को रेखांकित करता है?
3. What are the primary functions of administration?
प्रशासन के प्राथमिक कार्य क्या हैं?
4. What role does the National Commission for Women play in promoting women's rights in India?
भारत में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या भूमिका है?

5. What are the different types of Non-Governmental Organizations (NGOs)?

गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं?

6. Explain the origin and development of Self Help Groups (SHGs).

स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की उत्पत्ति और विकास को समझाइए।

7. How does civil society contribute to India's development and governance?

नागरिक समाज भारत के विकास और शासन में कैसे योगदान देता है?

8. What is a Citizen's Charter, and how does it contribute to improving the quality of public services and accountability in governance?

नागरिक चार्टर क्या है, और यह सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और शासन में उत्तरदायित्व को सुधारने में कैसे योगदान देता है?
